International Journal of Emerging Voices in Education
Volume 2 | Issue 6 | June 2026 | ISSN: 3107-958X (Online)
Available online at: https://ijeve.com/
DOI: https://doi.org/10.59828/ijeve.v2i6.61

पंडित दीनदयाल उपाध्याय के शैक्षिक विचार और राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों (1968, 1986, 2020) का एक तुलनात्मक अध्ययन

सैयद अब्दुल वाहिद शाह[1] & प्रोफेसर (डा.) अनीता सिंह[2]

[1]शोध छात्र, बी. एड. विभाग, बरेली कॉलेज, बरेली सम्बद्ध, महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय, बरेली

[1]Email: syadabdulwahid@gmail.com

[2]प्रोफेसर, बी. एड. विभाग, बरेली कॉलेज, बरेली सम्बद्ध, महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय, बरेली

[2]Email: anitasinghbly@gmail.com

Received: 02 June 2026 | **Accepted:** 13 June 2026 | **Published:** 30 June 2026

शोध सारांश

प्राचीन काल से ही शिक्षा प्रणाली में सुधार हेतु सतत प्रयास किये जाते रहे हैं। इन प्रयासों में अनेक ऋषि-मुनियों, शिक्षाविदों, समाज सुधारकों, मनीषियों, राजनेताओं का योगदान रहा है। प्रत्येक शैक्षिक काल खण्ड में भारतीय शिक्षा के उन्नयन हेतु सदैव प्रयास किये जाते रहे हैं। यह प्रयास भारतीय स्वतन्त्रता के पूर्व एवं पश्चात समय समय पर अनेक सरकारों द्वारा किये गये हैं। शिक्षा से सम्बन्धित सुधारों हेतु जो महापुरूष उल्लेखनीय हैं उनमें स्वामी विवेकानन्द, रविन्द्र नाथ टैगोर, अरविन्द घोष, पंडित मदन मोहन मालवीय, सर सैय्यद अहमद खां, डा0 जाकिर हुसैन, डा0 भीमराव अम्बेडकर, महात्मा गाँधी, इन्द्रिरा गाँधी एवं पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम सम्मलित किये जा सकते हैं। भारत के 15 अगस्त 1947 को स्वतन्त्र हो जाने के पश्चात अनेक शिक्षा आयोगों यथा राधा कृष्णनन आयोग, मुदालियर आयोग एवं कोठारी आयोग का गठन करके एवं उनके द्वारा प्रस्तुत सुझावों के आधार पर भारत की शिक्षा व्यवस्था में सुधार के प्रयास किये गये। सन 1968 में भारत की प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गयी जो शिक्षा के क्षेत्र में देश की शिक्षा व्यवस्था को व्यवस्थित करने का ठोस प्रयास था। इसके पश्चात सन 1986 में राष्ट्र की द्वितीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई, जिसे नई शिक्षा नीति 1986 कहा गया। इस शिक्षा नीति ने देश की शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तनों को लागू किया। इस शिक्षा नीति के 34 वर्षों के पश्चात राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू किया गया, जिसे तत्कालीन एन0डी0ए0 सरकार द्वारा लागू किया गया। देश की शिक्षा नीतियाँ पंडित दीनदयाल उपाध्याय के शैक्षिक विचारों से किस हद तक साम्य स्थापित करती हैं, प्रस्तुत शोध पत्र में इसका अध्ययन करने का प्रयास किया गया है, जिसके माध्यम से यह ज्ञात किया जा सके कि देश की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, 1986 एवं 2020 पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों से कितनी समानता एवं असमानता रखती हैं।

मुख्य शब्द:- *पंडित दीनदयाल उपाध्याय, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, भारतीय शिक्षा व्यवस्था, शैक्षिक विचार, शिक्षा सुधार, तुलनात्मक अध्ययन, भारतीय शिक्षा दर्शन।*

1. प्रस्तावना

मानवीय सभ्यता के इतिहास में शिक्षा को सदैव मनुष्य के आत्मिक, बौद्धिक और सामाजिक विकास का आधार रही है। स्वतन्त्रता के पश्चात देश की विकास यात्रा में शिक्षा नीतियों का निर्माण और क्रियान्वयन राष्ट्र के स्वरूप को सजाने-सवारने का सबसे सशक्त माध्यम रहा है। इस कार्य में अनेक विचारकों, शिक्षाविदों, राजनेताओं का अमूल्य योगदान रहा है। जिसमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय के 'एकात्म मानववाद' का दर्शन और उनके द्वारा प्रतिपादित शैक्षिक विचार एक मौलिक भारतीय प्रतिमान प्रस्तुत करते हैं । उपाध्याय जी का मानना था कि किसी भी राष्ट्र की प्रगति उसके अपनी राष्ट्रीय आत्मा और राष्ट्रीय प्राणशक्ति के जन-जागरण पर निर्भर करती है, और इस जागरण का प्राथमिक उपकरण शिक्षा ही है । प्रस्तुत शोध पत्र पंडित दीनदयाल उपाध्याय के शैक्षिक विचारों का अध्ययन करते हुए स्वाधीन भारत की तीनों राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों 1968, 1986 और 2020—का एक विस्तृत तुलनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करता है।

पंडित दीनदयाल उपाध्याय का एकात्म मानव दर्शन और शिक्षा के उद्देश्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय का शैक्षिक दृष्टिकोण उनके व्यापक राजनीतिक और सामाजिक दर्शन 'एकात्म मानववाद' (Integral Humanism) में गहराई से निहित है। यह दर्शन पश्चिमी विचारधराओं के भौतिकवादी और खंडित दृष्टिकोण के विकल्प के रूप में उदित हुआ, जो मनुष्य को केवल शरीर या केवल एक 'आर्थिक इकाई' के रूप में देखता है

This is an open access article under the Creative Commons Attribution-Non-Commercial 4.0 International License.
© The Author(s) 2026. IJEVE Published by Surya Multidisciplinary Publication.

। (उपाध्याय, पंडित दीनदयाल (2017). एकात्म मानववाद: तत्वमीमांसा और सिद्धांत चर्चा) उपाध्याय जी ने तर्क दिया कि मनुष्य शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा का एक समन्वित स्वरूप है, और वास्तविक प्रगति तभी संभव है जब इन चारों तत्वों का संतुलित विकास हो।

2. पुरुषार्थ चतुष्टय और सर्वांगीण विकास

पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के शैक्षिक दर्शन का केंद्रबिंदु 'पुरुषार्थ चतुष्टय' है—धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। (शर्मा, महेश चन्द्र (2016). दीनदयाल उपाध्याय सम्पूर्ण वाङ्मय) उनके अनुसार, शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो व्यक्ति को इन चारों लक्ष्यों की प्राप्ति में सक्षम बनाए । शिक्षा को केवल जीविकोपार्जन का साधन मानना उसकी गरिमा को कम करना है। यदि शिक्षा केवल 'अर्थ' (संपत्ति) पर केंद्रित होगी, तो वह स्वार्थ और संघर्ष को जन्म देगी; और यदि वह केवल 'काम' (इच्छाओं) की पूर्ति करेगी, तो समाज विलासिता में डूब जाएगा । अतः धर्म (नैतिक कर्तव्य) को आधार बनाकर अर्थ और काम का संतुलन स्थापित करना और अंततः मोक्ष (पूर्ण स्वतंत्रता) की ओर अग्रसर होना ही शिक्षा का वास्तविक मार्ग है ।

3. चिति और विराट की अवधारणा

पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने प्रत्येक राष्ट्र की अपनी एक प्रकृति और संस्कृति को 'चिति' के रूप में परिभाषित किया । उनके अनुसार, शिक्षा का मुख्य कार्य इस चिति को समझना और उसे सुरक्षित रखना है। जब राष्ट्र की यह अंतरात्मा जागृत होती है, तो 'विराट' नामक प्राणशक्ति का संचार होता है, जो समाज के अंगों को परस्पर जोड़कर एक जीवंत इकाई बनाता है । (उपाध्याय, पंडित दीनदयाल (2021). राष्ट्र चिंतन) भारतीय शिक्षा नीतियों का इतिहास इस चिति और विराट की खोज का ही इतिहास रहा है, जहाँ औपनिवेशिक मानसिकता को छोड़कर स्व-संस्कृति की ओर लौटने का निरंतर प्रयास किया गया है ।

4. मानव आयाम शैक्षिक लक्ष्य

पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का दृष्टिकोण शरीर स्वास्थ्य और कौशल शारीरिक शक्ति को धर्म का साधन बनाना मन संयम और भावना एकाग्रता और सांस्कृतिक संस्कारों का सिंचन बुद्धि ज्ञान और विवेक सत्य की खोज और स्वतंत्र चिंतन की क्षमता आत्मा शांति और मोक्ष स्वयं और सृष्टि के बीच एकात्मकता का अनुभव पंडित दीनदयाल उपाध्याय उपाध्याय जी के अनुसार शिक्षा के मौलिक सिद्धांत उपाध्याय जी ने शिक्षा को किसी व्यक्तिगत उपकार या राज्य के एहसान के रूप में नहीं, बल्कि एक अनिवार्य सामाजिक व्यवस्था के रूप में देखा। उनके विचारों में शिक्षा का भारतीयकरण केवल प्रतीकात्मक नहीं, बल्कि संरचनात्मक परिवर्तन की मांग करता है ।

5. शिक्षा: एक सामाजिक ऋण

भारतीय परंपरा में 'ऋषि ऋण' की संकल्पना अत्यंत महत्वपूर्ण है। उपाध्याय जी ने इसी संदर्भ में कहा कि शिक्षा प्रदान करना समाज का कर्तव्य है और शिक्षा प्राप्त करना प्रत्येक बालक का जन्मसिद्ध अधिकार । जब हम अगली पीढ़ी को शिक्षित करते हैं, तो हम उन पर कोई उपकार नहीं कर रहे होते, बल्कि अपने पूर्वजों से मिली ज्ञान की विरासत को आगे बढ़ाकर अपना ऋण चुका रहे होते हैं । (रानटा, रणधीर सिंह (2025). रेलेवेंस ऑफ़ दीनदयाल उपाध्याय' द एजुकेशनल आइडियाज) इस विचारधारा के कारण उन्होंने शिक्षा के व्यवसायीकरण का पुरजोर विरोध किया। उनका मानना था कि ज्ञान को 'बेचना' समाज के नैतिक पतन की पराकाष्ठा है ।

6. राज्य बनाम समाज:

शैक्षिक स्वायत्तता उपाध्याय जी ने इस बात पर विशेष बल दिया कि शिक्षा को 'सरकारीकरण' से मुक्त होना चाहिए । यद्यपि राज्य का कर्तव्य है कि वह शैक्षणिक संस्थानों के लिए संसाधन और वित्तीय सहायता प्रदान करे, लेकिन शिक्षा की सामग्री, पाठ्यक्रम और प्रबंधन पूरी तरह से विद्वानों, आचार्यों और शिक्षाविदों के हाथों में होना चाहिए । उन्होंने तर्क दिया कि जब शिक्षा राज्य के नियंत्रण में पूरी तरह चली जाती है, तो वह दलगत राजनीति और सरकारी विचारधारा का उपकरण बन जाती है, जिससे सत्य की स्वतंत्र खोज बाधित होती है ।

शिक्षक त्रयी की अनूठी संकल्पना शिक्षा की प्रक्रिया को उपाध्याय जी ने एक त्रिकोणीय व्यवस्था के रूप में देखा, जिसमें तीन प्रकार के गुरु और उनके माध्यम शामिल हैं : (शर्मा, विष्णु (2019) पंडित दीनदयाल उपाध्याय: जीवन और दर्शन)

माता (प्रथम गुरु): माध्यम 'संस्कार' है। बालक के चरित्र की नींव परिवार और सामाजिक परिवेश में पड़ती है।

आचार्य (द्वितीय गुरु): माध्यम 'शिक्षण' है। औपचारिक शिक्षा के केंद्र में शिक्षक की गरिमा को 'आचार्य देवो भव' के आदर्श पर पुनर्स्थापित करना अनिवार्य है ।

स्वयं व्यक्ति (तृतीय गुरु): माध्यम 'स्वाध्याय' है। जब तक विद्यार्थी स्वयं मनन और चिंतन (Self-study) नहीं करता, तब तक ज्ञान आत्मसात नहीं होता ।

7. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968:

स्वाधीन भारत की पहली बड़ी पहल स्वतंत्रता के दो दशक बाद, भारत ने अपनी पहली सुसंगत शिक्षा नीति 1968 में अपनाई। यह नीति कोठारी आयोग (1964-66) की व्यापक सिफारिशों का परिणाम थी, जिसका उद्देश्य 'शिक्षा का आमूलचूल पुनर्निर्माण' करना था । (गुप्ता अरूणा,

सिंह अरिमर्दन, 2019, समकालीन भारत एवं शिक्षा) प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल में घोषित इस नीति ने पहली बार शिक्षा को राष्ट्रीय एकता और आर्थिक विकास का अनिवार्य अंग माना ।

मुख्य प्रावधान और वैचारिक आधार 1968 की नीति का प्राथमिक लक्ष्य 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित करना था । इस नीति ने विज्ञान और गणित को स्कूली शिक्षा का अभिन्न अंग बनाया और कृषि शिक्षा पर विशेष बल दिया, जो उस समय के खाद्यान्न संकट और विकास की आवश्यकताओं को देखते हुए अनिवार्य था । उपाध्याय जी के 'स्वावलंबन' के विचार के अनुरूप, इस नीति ने शिक्षा को ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों तक पहुँचाने का संकल्प लिया ।

भाषा नीति और त्रि-भाषा सूत्र भाषा के प्रश्न पर 1968 की नीति ने त्रि-भाषा सूत्र (Three-Language Formula) को दृढ़ता से लागू करने का आह्वान किया । इसके तहत क्षेत्रीय भाषाओं के विकास को प्राथमिकता दी गई और हिंदी को संपर्क भाषा के रूप में विकसित करने पर जोर दिया गया । उपाध्याय जी ने भी सदैव 'स्वभाषा' में शिक्षा का समर्थन किया था, क्योंकि उनका मानना था कि विदेशी भाषा में शिक्षा प्राप्त करने से बालक की मौलिक चिंतन शक्ति क्षीण हो जाती है । 1968 की नीति ने इस दिशा में एक महत्वपूर्ण सैद्धांतिक आधार प्रस्तुत किया, यद्यपि इसके क्रियान्वयन में अनेक व्यावहारिक बाधाएं आईं ।

नीति घटक 1968 के प्रमुख प्रावधान वित्तीय संकल्प जीडीपी का 6% शिक्षा पर खर्च करने का लक्ष्य अनिवार्य शिक्षा 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा पाठ्यक्रम विज्ञान, गणित और कार्य-अनुभव (Work Experience) शिक्षक स्थिति वेतन और सेवा शर्तों में सुधार का प्रस्ताव उच्च शिक्षा क्षेत्रीय भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाना ।

8. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986:

आधुनिकीकरण और सामाजिक न्याय 1980 के दशक के मध्य तक भारत में तकनीकी क्रांति और सूचना प्रौद्योगिकी की लहर शुरू हो चुकी थी। इसी पृष्ठभूमि में प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नेतृत्व में 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाई गई । इस नीति का मूल मंत्र 'समानता के लिए शिक्षा' था, जहाँ समाज के हाशिए पर खड़े वर्गों—महिलाओं, अनुसूचित जातियों और जनजातियों—को मुख्यधारा में लाने का लक्ष्य रखा गया ।

'ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड' और बुनियादी ढांचा 1986 की नीति ने यह स्वीकार किया कि बिना बुनियादी सुविधाओं के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा संभव नहीं है। (सिंह कर्ण 2023, भारत में शिक्षा के समवर्ती मुद्दे) इसी उद्देश्य के लिए 'ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड' कार्यक्रम शुरू किया गया । इसका लक्ष्य प्रत्येक प्राथमिक स्कूल में कम से कम दो बड़े कमरे, आवश्यक शिक्षण सामग्री (नक्शे, चार्ट, खिलौने) और कम से कम दो शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित करना था । यह कदम उपाध्याय जी के उस विचार से मेल खाता था जहाँ उन्होंने समाज और राज्य की जिम्मेदारी मानी थी कि शिक्षा के लिए 'देश और काल' के अनुकूल वातावरण तैयार किया जाए ।

नवोदय विद्यालय और ग्रामीण प्रतिभा ग्रामीण क्षेत्रों की मेधावी प्रतिभाओं को निखारने के लिए 'नवोदय विद्यालयों' की स्थापना 1986 की नीति की एक क्रांतिकारी पहल थी । ये आवासीय विद्यालय सामाजिक न्याय और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के एक अनूठे संगम के रूप में उभरे। उपाध्याय जी के 'अंत्योदय' के सिद्धांत के अनुसार, समाज के अंतिम व्यक्ति तक शिक्षा की उच्चतम गुणवत्ता पहुँचाना आवश्यक है । नवोदय विद्यालयों ने गरीब परिवारों के बच्चों को वह अवसर प्रदान किए जो पहले केवल शहरी उच्च वर्ग तक सीमित थे ।

10+2+3 की संरचना और व्यावसायिक शिक्षा इस नीति ने देश भर में एक समान शिक्षा संरचना 10+2+3 (दस वर्ष की स्कूली शिक्षा, दो वर्ष की उच्च माध्यमिक और तीन वर्ष का स्नातक) को मजबूती से लागू किया गया इसके साथ ही साथ माध्यमिक स्तर पर 'व्यावसायिक शिक्षा' (Vocationalization) पर जोर दिया गया ताकि छात्र अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद स्वावलंबी बन सकें । (गुप्ता अरूणा, सिंह अरिमर्दन, 2019, समकालीन भारत एवं शिक्षा) हालाँकि, बाद के वर्षों में यह पाया गया कि व्यावसायिक शिक्षा मुख्यधारा से अलग-थलग रह गई और इसमें रटने की प्रवृत्ति कम नहीं हुई ।

9. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020:

21वीं सदी का भारतीय पुनर्जागरण तीन दशकों से अधिक समय के बाद, वर्ष 2020 में भारत ने एक नई शिक्षा नीति अपनाई जो न केवल वैश्विक मानकों को ध्यान में रखती है, बल्कि भारतीय संस्कृति और मूल्यों पर भी आधारित है । (सिंह कर्ण 2023, भारत में शिक्षा के समवर्ती मुद्दे) डॉ. के. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता वाली समिति ने 'शिक्षा के भारतीयकरण' के उस सपने को साकार करने का खाका तैयार किया, जिसकी वकालत पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने दशकों पहले की थी ।

5+3+3+4 का नया शैक्षणिक ढांचा NEP 2020 ने पुरानी 10+2 प्रणाली को पूरी तरह से बदल दिया है। नया ढांचा बच्चे के मस्तिष्क के विकास के वैज्ञानिक चरणों पर आधारित है :

फाउंडेशनल स्टेज (उम्र 3-8): इसमें आंगनबाड़ी/प्री-स्कूल को पहली बार स्कूली ढांचे में शामिल किया गया है। यहाँ शिक्षा का आधार खेल और गतिविधि आधारित है ।

प्रिपेरेटरी स्टेज (उम्र 8-11): यहाँ पढ़ने-लिखने और गणितीय कौशलों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है ।

मिडल स्टेज (उम्र 11-14): इस स्तर पर कोडिंग और व्यावसायिक इंटर्नशिप की शुरुआत होती है, जो उपाध्याय जी के 'कौशल विकास' और 'आत्मनिर्भरता' के विचारों के अनुरूप है ।

सेकेंडरी स्टेज (उम्र 14-18): यहाँ विषयों के बीच का सख्त अंतर (जैसे कला बनाम विज्ञान) समाप्त कर दिया गया है।

10. बहुविषयक और समग्र शिक्षा (Holistic Education)

पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का 'एकात्म मानव' खंडित नहीं बल्कि समग्र विकास का पक्षधर था। NEP 2020 इसी सिद्धांत को अपनाते हुए 'बहुविषयक शिक्षा और अनुसंधान विश्वविद्यालयों' (MERU) की अवधारणा प्रस्तुत करती है । अब एक छात्र भौतिक विज्ञान के साथ संगीत या दर्शनशास्त्र भी पढ़ सकता है। यह ज्ञान को एक अखंड इकाई के रूप में देखने की भारतीय दृष्टि को पुनर्स्थापित करता है । (कस्तूरीरंगन, के. (2019). ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी: बहुविषयक दृष्टिकोण)

मातृभाषा और स्व-संस्कृति पर गर्व इस नीति का सबसे महत्वपूर्ण पहलू प्राथमिक शिक्षा को मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में प्रदान करने की सिफारिश है । उपाध्याय जी का मानना था कि जिस प्रकार विदेशी खून किसी के शरीर को पोषण नहीं दे सकता, उसी प्रकार विदेशी भाषा के माध्यम से दी गई शिक्षा बालक के मानसिक विकास को पंगु बना देती है । 2020 की नीति भारत की भाषाई विविधता को 'सजा' नहीं बल्कि एक 'संपत्ति' मानती है ।

तुलना का आधार 1968 की नीति 1986 की नीति 2020 की नीति संरचना लचीली / राज्यवार 10 + 2 + 3 5 + 3 + 3 + 4 मूल दर्शन राष्ट्रीय एकता सामाजिक समानता आत्मनिर्भरता और भारतीयता व्यावसायिक शिक्षा गौण / कार्य-अनुभव माध्यमिक स्तर पर अलग कक्षा 6 से मुख्यधारा में भाषा माध्यम त्रि-भाषा सूत्र त्रि-भाषा सूत्र मातृभाषा/क्षेत्रीय भाषा पर बल उच्च शिक्षा विस्तार पर ध्यान गुणवत्ता और प्रबंधन शोध और लचीलापन (ABC) मूल्यांकन वार्षिक परीक्षाएं वर्णनात्मक वार्षिक परीक्षा दक्षता आधारित / सेमेस्टर

उपाध्याय जी के विचारों और राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों का गहन तुलनात्मक विश्लेषण उपाध्याय जी के विचारों और इन तीनों नीतियों का विश्लेषण करने पर एक क्रमिक विकास दिखाई देता है, जहाँ शिक्षा व्यवस्था धीरे-धीरे औपनिवेशिक बोझ को उतारकर अपनी सांस्कृतिक जड़ों की ओर लौट रही है। (रानटा, रणधीर सिंह, और ठाकुर, हरीश कुमार (2024). इम्पैक्ट ऑफ़ दीनदयाल उपाध्याय' द आइडियाज ऑन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी)

11. व्यक्ति के स्वरूप की समझ:

खंडित बनाम एकीकृत 1968 और 1986 की नीतियां मुख्य रूप से मनुष्य को एक 'नागरिक' और 'उत्पादक इकाई' के रूप में देखती थीं । उनका ध्यान साक्षरता दर बढ़ाने और औद्योगिक विकास के लिए श्रम शक्ति तैयार करने पर अधिक था। इसके विपरीत, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने मनुष्य को शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा के योग के रूप में देखा था । NEP 2020 इस दिशा में एक बड़ा बदलाव है। यह नीति 'समग्र स्वास्थ्य' (Physical and Emotional Well-being) और 'नैतिक मूल्यों' को शिक्षा के परिणामों (Learning Outcomes) का हिस्सा बनाती है, जो उपाध्याय जी के 'एकात्म विकास' के सिद्धांत के पूर्णतः अनुरूप है ।

12. व्यावसायिक शिक्षा और आर्थिक लोकतंत्र

1- पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का आर्थिक दर्शन 'हर हाथ को काम' पर आधारित था, जिसे उन्होंने 'आर्थिक लोकतंत्र' कहा । उनका मानना था कि शिक्षा ऐसी हो जो व्यक्ति को केवल नौकरी खोजने वाला (Job Seeker) नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर बनाए। (गुप्त, बजरंग लाल, 2007, पंडित दीनदयाल का आर्थिक चिन्तन)

1968: कार्य-अनुभव (Work Experience) को एक शौक के रूप में देखा गया ।

1986: व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को शैक्षणिक रूप से 'कमजोर' छात्रों के लिए एक अलग विकल्प के रूप में पेश किया गया ।

2020: व्यावसायिक शिक्षा को सभी के लिए अनिवार्य बनाकर गरिमा प्रदान की गई है। कक्षा 6 से 'बगलेस डेज' और स्थानीय कारीगरों के साथ इंटर्नशिप की व्यवस्था सीधे उपाध्याय जी के 'ग्राम स्वावलंबन' के विचार को पुष्ट करती है ।

भाषा और सांस्कृतिक गौरव: स्वभाषा बनाम अंग्रेजी उपाध्याय जी ने चेतावनी दी थी कि "ब्रिटिश राज खत्म हो गया है लेकिन पश्चिमीकरण प्रगति का पर्याय बन गया है" । उन्होंने अंग्रेजी के वर्चस्व को 'बौद्धिक गुलामी' माना था।

1968 और 1986 की नीतियों में त्रि-भाषा सूत्र के बावजूद अंग्रेजी माध्यम के 'पब्लिक स्कूलों' का वर्चस्व बना रहा, जिससे समाज में दो श्रेणियां बन गईं—शिक्षित अभिजात वर्ग और सामान्य वर्ग ।

उपाध्याय जी ने 'पब्लिक स्कूलों' को 'अखिल भारतीय विनाशकारी' प्रभाव वाला बताया था ।

NEP 2020 पहली बार स्पष्ट रूप से 'मातृभाषा' में प्रारंभिक शिक्षा की अनिवार्यता और उच्च शिक्षा (इंजीनियरिंग, चिकित्सा) को भारतीय भाषाओं में शुरू करने की बात करती है। यह भाषाई न्याय की दिशा में उपाध्याय जी के विजन की एक बड़ी जीत है ।

13. शिक्षक की भूमिका और स्वायत्तता

पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने शिक्षकों को सरकारी कर्मचारी के बजाय 'समाज का निर्माता' माना था और उन्हें प्रशासनिक बेड़ियों से मुक्त करने का आह्वान किया था ।

1968 और 1986 की नीतियों ने शिक्षक प्रशिक्षण (Teacher Training) पर बल दिया, लेकिन नौकरशाही का नियंत्रण बना रहा । (सिंह कर्ण 2023, भारत में शिक्षा के समवर्ती मुद्दे)

NEP 2020 संस्थानों को 'ग्रेडेड ऑटोनॉमी' (Graded Autonomy) देने और आचार्यों को स्वयं अपना पाठ्यक्रम और शोध दिशा निर्धारित करने की छूट देने का वादा करती है । यह व्यवस्था उपाध्याय जी के 'स्वायत्त शैक्षिक निकायों' (Autonomous Educational Bodies) के सपने के करीब है ।

अंत्योदय और समावेशी शिक्षा: नीतियों का मानवीय पक्ष पंडित दीनदयाल उपाध्याय का सबसे प्रभावी विचार 'अंत्योदय' है—पंक्ति के अंतिम व्यक्ति का उत्थान । शिक्षा के संदर्भ में इसका अर्थ है कि सबसे गरीब और सबसे दूरदराज के क्षेत्र में रहने वाले बालक को भी वही शिक्षा मिले जो राजधानी में रहने वाले धनी बालक को मिलती है।

सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित समूह (SEDG) NEP 2020 ने 'अंत्योदय' की भावना को औपचारिक रूप देते हुए 'सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित समूहों' (SEDG) की पहचान की है । इसके लिए विशेष शिक्षा क्षेत्रों (Special Education Zones) की स्थापना का प्रस्ताव है जहाँ अधिक संसाधन दिए जाएंगे।

1986 की नीति में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए छात्रवृत्तियों का प्रावधान था, जो 'पहुँच' (Access) पर केंद्रित था ।

2020 की नीति 'पहुँच' के साथ-साथ 'सफल अधिगम' (Successful Learning) पर केंद्रित है, ताकि कोई बच्चा केवल स्कूल न आए, बल्कि वास्तव में सीखे और आगे बढ़े ।

एकलव्य आवासीय विद्यालय और जनजातीय शिक्षा उपाध्याय जी ने जनजातीय समाज को 'हमारे ही शरीर का हिस्सा' माना था । 2020 की नीति और वर्तमान में क्रियान्वित 'एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय' (EMRS) इसी दर्शन को आगे बढ़ाते हैं । ये स्कूल उन क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुँचा रहे हैं जहाँ पहले कभी शिक्षा का प्रकाश नहीं पहुँचा था, जो कि अंत्योदय की वास्तविक सिद्धि है ।

14. चरित्र निर्माण और राष्ट्र निर्माण: शिक्षा की नैतिक धुरी

पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अनुसार, "शिक्षा केवल विद्यालय की गतिविधि नहीं है, बल्कि एक संपूर्ण सामाजिक प्रक्रिया है" । उनका मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य केवल डिग्रियां बांटना नहीं, बल्कि 'चरित्र निर्माण' (Character Building) करना है ।

मूल्यों पर आधारित शिक्षा 1986 की नीति में 'मानवीय मूल्यों' की बात कही गई थी, लेकिन वे अक्सर पाठ्यपुस्तकों के अंत में कुछ वाक्यों तक सीमित रहे । NEP 2020 ने 'संवैधानिक मूल्यों' और 'भारतीय ज्ञान परंपरा' (IKP) को पाठ्यक्रम की मुख्यधारा में शामिल किया है । इसमें सेवा, अहिंसा, सत्य और स्वच्छता जैसे मूल्यों को व्यवहार में उतारने की बात कही गई है, जो उपाध्याय जी के 'संस्कार' आधारित शिक्षा की याद दिलाते हैं ।

राष्ट्र के प्रति कर्तव्य उपाध्याय जी ने कहा था कि स्वतंत्रता तभी सार्थक है जब वह हमारी संस्कृति की अभिव्यक्ति का साधन बने । 2020 की नीति छात्रों में राष्ट्र के प्रति गौरव और वैश्विक नागरिक (Global Citizen) बनने की संतुलित भावना विकसित करने का लक्ष्य रखती है । यह 'चिति' के आधार पर 'विराट' को सशक्त करने का व्यावहारिक मार्ग है ।

15. निष्कर्ष:

एक राष्ट्र-केंद्रित शैक्षिक भविष्य की ओर पंडित दीनदयाल उपाध्याय के शैक्षिक विचारों और भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों (1968, 1986, 2020) का तुलनात्मक अध्ययन यह प्रकट करता है कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था ने औपनिवेशिक छाया से बाहर निकलने के लिए एक लंबा और कठिन संघर्ष किया है। जहाँ 1968 की नीति ने बुनियादी ढांचे की नींव रखी और 1986 की नीति ने समानता और तकनीक को जोड़ा, वहीं 2020 की शिक्षा नीति उस 'मूलाधार' को वापस लाई है जिसकी वकालत उपाध्याय जी ने 'एकात्म मानववाद' के माध्यम से की थी ।

उपाध्याय जी का विजन—शिक्षा के माध्यम के रूप में मातृभाषा, व्यावसायिक कौशल के माध्यम से आत्मनिर्भरता, राज्य के नियंत्रण से मुक्ति, और चरित्र निर्माण के माध्यम से अंत्योदय—अब केवल राजनीतिक विचार नहीं बल्कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रमुख स्तंभ बन चुके हैं । इस नीति की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि हम इसे 'सरकारी आदेश' के बजाय 'सामाजिक आंदोलन' के रूप में कितना स्वीकार करते हैं। यदि हम उपाध्याय जी की 'शिक्षक त्रयी' (माता, आचार्य और स्वाध्याय) के महत्व को समाज में पुनः स्थापित कर पाए, तो भारत का भविष्य निश्चित रूप से उज्ज्वल और स्वावलंबी होगा ।

यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि 2020 की शिक्षा नीति पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सपनों का शैक्षिक घोषणापत्र है। अब समय आ गया है कि शिक्षा को 'अर्थ' और 'काम' के संघर्ष से निकालकर 'धर्म' के आधार पर 'मोक्ष' यानी पूर्ण स्वतंत्रता और ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाया जाए । अंततः, शिक्षा का यही भारतीय प्रतिमान विश्व के लिए भी एक मार्गदर्शक प्रकाश स्तंभ बनेगा ।

संन्दर्भ ग्रन्थ सूची :-

[1]. उपाध्याय, पंडित दीनदयाल (2017). एकात्म मानववाद: तत्वमीमांसा और सिद्धांत चर्चा. नई दिल्ली: प्रभात प्रकाशन।

[2]. शर्मा, महेश चन्द्र (2016). दीनदयाल उपाध्याय सम्पूर्ण वाङ्मय (15 खंड). नई दिल्ली: प्रभात प्रकाशन।

[3]. उपाध्याय, पंडित दीनदयाल (2021). राष्ट्र चिंतन. लखनऊ: लोकहित प्रकाशन।

[4]. गुप्ता अरूणा, सिंह अरिमर्दन, 2019, समकालीन भारत एवं शिक्षा, ठाकुर पब्लिकेशन, प्रा0 लि0, पृष्ठ सं0-110-119

[5]. सिंह कर्ण 2023, भारत में शिक्षा के समवर्ती मुद्दे, गोविन्द प्रकाशन, लखीपुरी खीरी, पृष्ठ सं0-180-184 एवं पृष्ठ सं0-214 से 217

[6]. गुप्त, बजरंग लाल, 2007, पंडित दीनदयाल का आर्थिक चिन्तन, सुरूचि प्रकाशन नई दिल्ली
[7]. रानटा, रणधीर सिंह, और ठाकुर, हरीश कुमार (2024). इम्पैक्ट ऑफ़ दीनदयाल उपाध्याय' द आइडियाज ऑन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी. शिमला: हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय।उपाध्याय, पंडित दीनदयाल
[8]. (1965). भारतीय अर्थनीति: विकास की एक दिशा. लखनऊ: राष्ट्रधर्म प्रकाशन।
[9]. विजन आईएएस. (2025). एकात्म मानववाद (एकात्म मानव दर्शन). मंथली मैगज़ीन, 22 जुलाई 2025।
[10]. उपाध्याय, पंडित दीनदयाल (2017). एकात्म मानववाद के प्रणेता दीनदयाल उपाध्याय. नई दिल्ली: प्रभात प्रकाशन।
[11]. रानटा, रणधीर सिंह (2025). रेलेवेंस ऑफ़ दीनदयाल उपाध्याय' द एजुकेशनल आइडियाज इन द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी (NEP) 2020. रिसर्चगेट।
[12]. विद्या भारती. (2021). भारतीय शिक्षा: पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचार विद्या भारती पोर्टल।
[13]. शिक्षा मंत्रालय. (2020). राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020. भारत सरकार।
[14]. शिक्षा मंत्रालय. (1968). राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968. भारत सरकार।
[15]. शिक्षा मंत्रालय. (1986). राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986. भारत सरकार।
[16]. कोठारी आयोग. (1966). शिक्षा और राष्ट्रीय विकास: रिपोर्ट (1964-66). भारत सरकार।
[17]. शिक्षा मंत्रालय. (1968). त्रि-भाषा सूत्र और भाषाई विकास. भारत सरकार।
[18]. गांधी, रा. (1986). राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986: समानता के लिए शिक्षा. भारत सरकार।
[19]. शिक्षा मंत्रालय. (1986). अनुसूचित जाति एवं जनजाति शिक्षा हेतु विशेष प्रावधान. भारत सरकार।
[20]. भारत सरकार. (1987). ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड: प्राथमिक शिक्षा सुधार योजना. शिक्षा मंत्रालय।
[21]. शिक्षा मंत्रालय. (1986). नवोदय विद्यालय समिति: ग्रामीण प्रतिभा विकास।
[22]. रिसर्चगेट. (2023). रिफॉर्म एंड रियलिटी: एनईपी 2020 वर्सेस एनपीई 1986।
[23]. कस्तूरीरंगन, के. (2019). ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी: बहुविषयक दृष्टिकोण. भारत सरकार।
[24]. ठाकुर, हरीश कुमार (2024). पंडित दीनदयाल उपाध्याय और नई शिक्षा नीति का दर्शन।
[25]. शिक्षा मंत्रालय. (2020). 5+3+3+4 स्कूली संरचना का विवरण. भारत सरकार।
[26]. इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ सोशल इम्पैक्ट. (2022). कम्पैरेटिव एनालिसिस ऑफ़ एनपीई 1986 एंड एनईपी 2020।
[27]. विद्या भारती. (2024). शिक्षा का भारतीयकरण: लक्ष्य और सिद्धि।
[28]. ललित कुमार, डॉ. (2016). दीनदयाल उपाध्याय के विचार और चरित्र निर्माण शिक्षा. पटना ट्रेनिंग कॉलेज।

Cite this Article:

सैयद अब्दुल वाहिद शाह, & अनीता सिंह (2026). पंडित दीनदयाल उपाध्याय के शैक्षिक विचार और राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों (1968, 1986, 2020) का एक तुलनात्मक अध्ययन. International Journal of Emerging Voices in Education, 2(6), 1–6.

Journal URL: *https://ijeve.com/* ***DOI:*** *https://doi.org/10.59828/ijeve.v2i6.61*